

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय डप्टी क मश्नर - प्रथम (कर निर्धारण) हल्द्वानी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय डप्टी क मश्नर - प्रथम (कर निर्धारण) हल्द्वानी के माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अजय कुमार मश्रा सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री र व भूषण ले.प. द्वारा दिनांक 08.12.2017 से 18.12.2017 तक श्री अशोक कुमार वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

#### भाग-I

1. परिचयात्मक: इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री वनय कुमार द्विवेदी एवं श्री अंशुमन अग्रवाल सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 25.01.2017 से 03.02.2017 तक तक श्री अशोक कुमार वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2015 से 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: कर संग्रह

(ii)(अ) राजस्व ववरण:

वगत तीन वर्षों में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (रुलाख में)
2014-15	8243.80
2015-16	10723.89
2016-17	11147.83

(II) (ब) बजट का ववरण:- वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

वर्ष	बजट आवंटन		व्यय		बचत	
	आयोज नागत	आयोजनेतर	आयोजनागत	आयोजनेतर	आयोजनागत	आयोजनेतर
2014-15						
2015-16				शून्य		
2016-17						

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय अ धक्य (+)	बचत (-)
शून्य					

(iii) इकाई को बजट आवंटन इकाई द्वारा आहरण वतरण का कार्य नहीं किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई .....A श्रेणी की है।

(iv) वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

स चव- ए डशनल क मशर- ज्वाइन्ट क मशर - डप्टी क मशर - सहायक आयुक्त- वा णज्य कर अ धकारी

(v) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व ध: लेखापरीक्षा में कार्यालय डप्टी क मशर - प्रथम (कर निर्धारण) हल्द्वानी को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय डप्टी क मशर - प्रथम (कर निर्धारण) हल्द्वानी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) वस्तुतः जांच हेतु माह का चयन :

राजस्वा: माह 03/2017 को वस्तुतः जांच हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(viii) लेखापरीक्षा भारत के संवधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

## भाग-दो "ब"

प्रस्तर सं० :- 01 अर्थदण्ड का अनारोपण ₹0.69 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा-58 की उपधारा-8 के अनुसार देय कर बिना किसी कारण के बिलम्ब से जमा करने पर देय कर का कम से कम दस प्रतिशत किन्तु अधिकतम 25 प्रतिशत यदि कर दस हजार रुपये तक हों और देय कर का 50 प्रतिशत यदि देय कर दस हजार रुपये से अधिक हो का प्रावधान किया गया है।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर-प्रथम वाणिज्य कर हल्द्वानी के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि लेखापरीक्षा अवधि माह 04/2016 से माह 03/2017 तक में निम्नलिखित व्यौहारियों द्वारा अपने देय कर बिलम्ब से जमा किया जाना पाया गया:-

क्र० सं०	व्यौहारी का नाम एवं पता	कर निर्धारण वर्ष	कर की देय तिथि	जमा की दिनांक	धनराशि रुपये में	अर्थदण्ड रुपये में
1.	सर्वश्री अम्बिका आटोव्हील्स प्रा०लि० हल्द्वानी	2012-13	12/2012 03/2013	29.01.13 27.12.13	521320.00 11840.00	52132.00 1184.00
2.	सर्वश्री जय मोटर्स हल्द्वानी	2014-15	06/2014	31/07/14	156678.00	15668.00
<b>योग</b>					<b>869838.00</b>	<b>68984.00</b>

उक्त ₹.68984.00 अनारोपित अर्थदण्ड के सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा द्वारा झुंगित किये जाने पर विभाग द्वारा परीक्षणोंपरान्त कार्यवाही किये जाने की टिप्पणी की गयी।

अतः अनारोपित अर्थदण्ड ₹ 68984.00.00 का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

## भाग-दो "ब"

प्रस्तर सं० :- 02 अनियमित आईटीसी एवं अर्थदण्ड ₹0.71 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की अनुसूची-दो (ख) के क्रमांक 105 के अनुसार सभी प्रकार और सभी रुपों में मसालों की बिक्री पर पाँच प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय होगा, साथ ही धारा 58 की उपधारा (1)(XI) के अनुसार कोई व्यापारी इनपुट टैक्स के लाभ के रूप में कसी धनराश का गलत दावा करता है तो ₹5000 या दावाकृत धनराश का तीन गुना, जो भी अधिक हो अर्थदण्ड का दायी होगा।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर-प्रथम वाणिज्य कर हल्द्वानी के अभिलेखों के अनुसार ब्यौहारी सर्व श्री मानक चन्द एण्ड संन्स हल्द्वानी एक पंजीकृत ब्यौहारी है। ब्यौहारी के कारोबार वर्ष 2013-14 को कर निर्धारण आदेश धारा 25(7) के अन्तर्गत दिनांक 04-03-2017 द्वारा निस्तारित किया गया। करनिर्धारण आदेश व पत्रावली की जाँच के दौरान पाया गया कि मसालों की खरीद पर 13.5 प्रतिशत की दर से आईटीसी दिया गया।

क्र० सं०	दिनांक	क्रय की गयी सामग्री	धनराशि रु. में	क्लेम की गयी आईटीसी	आईटीसी जो देय थी	वापसी योग्य आईटीसी
1.	01.01.14	मसाले	27416.00	3701.00	1370.80	2330.20
2.	20.03.14	तदैव	74516.00	10060.00	3725.80	6334.20
3.	27.03.14	तदैव	72269.00	9756.00	3613.45	6142.55
4.	28.03.14	तदैव	35354.00	4773.00	1767.70	3005.50
<b>योग</b>						<b>17812.25</b>

उक्त ₹17812.25 अनियमित आईटीसी एवं अर्थदण्ड ₹53436.75 कुल वापसी योग्य धनराशि ₹71249 (₹53436.75+₹17812.25) थी, जिसके सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा परीक्षणोपरान्त कार्यवाही किये जाने की टिप्पणी की गयी।

अतः ₹71249 की राजस्व क्षति का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

## भाग-दो "ब"

प्रस्तर सं० :-03 कर की अनियमित छूट ₹2.05 लाख।

केन्द्रीय बिक्री कर नियमावली के नियम 12(8) (क) के अनुसार प्राधिकृत व्यक्ति प्रपत्र सी के घोषणा पत्र को हस्ताक्षरित व प्रमाणित करेगा तथा प्रमाण-पत्र को उपबन्धित रीति से सत्यापन करेगा। अर्थात् घोषणा पत्र में यदि किन्ही कारणों से कटिंग की जाती है तो उस पर प्रतिहस्ताक्षरित करेगा।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर-प्रथम वाणिज्य कर हल्द्वानी के अभिलेखों के अनुसार ब्यौहारी सर्व श्री शारदा इण्डस्ट्रीज हल्द्वानी एक पंजीकृत ब्यौहारी है। ब्यौहारी के कारोबार वर्ष 2013-14 को कर निर्धारण आदेश धारा 9(2) के अन्तर्गत दिनांक 04-03-2017 द्वारा निस्तारित किया गया। कर निर्धारण आदेश व पत्रावली की जाँच के दौरान पाया गया कि ब्यौहारी द्वारा प्रपत्र सी० सं० पी०बी०/ए/सी-8732168 के बिरुद्ध ₹1778432.00 का रोजिन तारपीन की बिक्री की गयी किन्तु दिनांक 13.08.14 व 09.09.14 के स्थान पर ओवर राइटिंग करते हुए 13.08.13 व 09.09.13 किया गया, किन्तु इसे सम्बन्धित द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं किया गया। उक्त प्रपत्र पर उल्लिखित धनराशि ₹1778432.00 पर नियमानुसार छूट अनुमन्य नहीं थी। चूं क व्यापारी द्वारा रेटिन तारपीन पर 13.5 प्रतिशत की दर से बिक्री स्वीकार की गयी है। अतः अन्तरीय दर 11.5 प्रतिशत (13.5-2) से . ₹204519.68 (1778432×11.5%) अनियमित छूट दिये जाने के सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा द्वारा झंगित किये जाने पर विभाग द्वारा परीक्षणोपरान्त कार्यवाही किये जाने की टिप्पणी की गयी।

अतः अनियमित कर छूट ₹204520 का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

**भाग-III**

राजस्व से संबंधित वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तारों का ववरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
	शून्य	

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तारों की अनुपालन आख्या : शून्य

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तारों का ववरण : शून्य

**भाग-IV**

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

## भाग-V

आभार

- कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय डप्टी कमिश्नर - प्रथम (कर निर्धारण) हल्द्वानी तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथा प लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
- सतत् अनियमितताएं:  
टिप्पणी- शून्य
- लेखापरीक्षा अवध में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं०	नाम	पदनाम	अवध
(i)	श्री राकेश वर्मा	डी०सी०	01.04.16 से 20.07.16 तक
(ii)	श्री निशीकान्त सिंह	डी०सी०	20.07.16 से 24.08.16 तक
(iii)	श्री राहुल वर्मा	डी०सी०	24.08.16 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय डप्टी कमिश्नर - प्रथम (कर निर्धारण) हल्द्वानी को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/प महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र